

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक
(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

105 / 2017
05.12.2017

- 1-रामबिलास पुत्र जंसी जाति मीना निवासी तुम्बीपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज०
2-मोरपाल पुत्र जंसी जाति मीना निवासी तुम्बीपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज०
-अपीलांट्स

बनाम

नायब तहसीलदार बनेठा जिला-टोंक

-रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 24.10.2017 मिसल नम्बर 1503 / 2017

- उपस्थिति : (1) श्री राजकुमार मीणा, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट

निर्णय


दिनांक 01.08.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने निर्णय दिनांक 24.10.2017 के द्वारा अपीलांट्स को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 131 रकबा 0.36 है० मे से रकबा 0.04 है० किस्म बाराणी-2 वाके ग्राम तुम्बीपुरा तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर बाडा बनाकर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 1200/रु. पेनल्टी कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलांट्स ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलांट्स का उक्त आराजी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध या सरोकार नहीं है। अपीलांट्स द्वारा सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण कर बाडे का भी निर्माण नहीं किया है। अपीलांट्स के विरुद्ध रिपोर्ट पेश की है। तथाकथित आराजी अपीलांट्स के खातेदारी की भूमि के पास होने से जानवरो का थोडा सा चारा उक्त भूमि पर डाल रखा था। अपीलांट्स के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व




जिला कलेक्टर
टोंक

वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मगवाई और न मौके का निरीक्षण किया गया। अपीलान्ट्स ने कब्जा छोड़ने वावत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

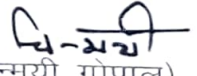
अपीलान्ट्स के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट्स को विवादित भूमि खसरा नम्बर 131 रकबा 0.36 है 0 में से 0.04 है 0,किस्म वारानी-2 वाके ग्राम तुम्बीपुरा तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर बाड़े बनाने पर नायब तहसीलदार वनेटा द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर 60 दिवस की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयान से सिद्ध है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट्स की ओर से लाला की तामील हुई है। अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट्स द्वारा भूमि खसरा नम्बर 131 रकबा 0.36 है 0 में से 0.04 है 0 किस्म वारानी-2 वाके ग्राम तुम्बीपुरा तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कब्जा जोत कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट्स द्वारा दिनांक 28.12.2017 को न्यायालय हाजा में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त आराजी पर हमारा कोई कब्जा अथवा अतिक्रमण नहीं है और ना ही कभी हमने उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया है,उक्त भूमि पर हमारा कोई पुख्ता निर्माण भी नहीं है और ना ही भविष्य में कोई पुख्ता निर्माण करेगे। नायब तहसीलदार वनेटा ने उनके पत्र क्रमांक 1666 दिनांक 16.03.2021 से रिपोर्ट प्रेषित की है कि वर्तमान में आ0ख0नं0 131 पर अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार वनेटा का निर्णय दिनांक 24.10.2017 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्ट पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(विन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
दो.क